

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
08.02.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1029 का उत्तर

तमिलनाडु में चालू रेल परियोजनाएं

1029. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय बजट में तमिलनाडु राज्य के लिए घोषित उन रेल परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है जिनका अभी तक निष्पादन नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए आवंटित/व्यय की गई निधि के साथ-साथ अप्रयुक्त निधि का परियोजना-वार विवरण कारण सहित क्या है;
- (ग) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में होने वाली देरी के क्या कारण हैं; और
- (घ) इन परियोजनाओं की लागत में और अधिक बढ़ोतरी से बचने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा दें?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

तमिलनाडु में चालू रेल परियोजनाओं के संबंध में 08.02.2023 को लोक सभा में डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. के अतारांकित प्रश्न सं. 1029 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं को क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत और शुरू किया जाता है, न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। बहरहाल, 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में घोषित की गई तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 30,692 करोड़ रुपए की लागत वाली 2,944 किमी लंबाई की 24 रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (09 नई लाइन, 4 आमान परिवर्तन और 11 दोहरीकरण परियोजनाएं) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 804 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2022 तक 7,705 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- 10,724 करोड़ रुपए की लागत और 871 किमी की कुल लंबाई की 9 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 18 किमी लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2022 तक 685 करोड़ रुपए तक का व्यय किया जा चुका है।
- 5,778 करोड़ रुपए की लागत और 839 किमी की लंबाई की 4 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिसमें से 622 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2022 तक 3,179 करोड़ रुपए तक का व्यय किया जा चुका है।
- 14,190 करोड़ रुपए की लागत और 1,234 किमी की लंबाई की 11 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिसमें से 164 किमी लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2022 तक 3,841 करोड़ रुपए तक का व्यय किया जा चुका है।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2021-22 और मौजूदा वित्त वर्ष अर्थात् 2022-23 के दौरान तमिलनाडु राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 908 कि.मी. कुल लंबाई की कुल 10 परियोजनाओं (01 नई लाइन और 09 दोहरीकरण) को बजट में घोषित/शामिल किया गया है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं दक्षिण रेलवे(द.रे.) , दक्षिण मध्य रेलवे(द.म.रे.) और दक्षिण पश्चिम रेलवे (द.प.रे.), के तहत कवर की जाती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का जोन-वार और वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात्

www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways>Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance (Budget) >Rail Budget/Pink Book (Year)> Railway wise Works Machinery and Rolling Stock Programmeपर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

2014 से, भारतीय रेल में अवसंरचनात्मक और संरक्षा कार्यों संबंधी परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन और तदनुरूपी कमिश्निंग में काफी वृद्धि हुई है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाले अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन को 2009-14 के दौरान 879 करोड़ रु. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2014-19 के दौरान 1,979 करोड़ रु. प्रति वर्ष किया गया है (2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट आवंटन से 125% अधिक)। इन परियोजनाओं पर वार्षिक बजट आवंटनों को वित्त वर्ष 2019-20 में 2,410 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक आवंटन से 174% अधिक), वित्त वर्ष 2020-21 में 2,812 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 220% अधिक) और वित्त वर्ष 2021-22 में 3,730 करोड़ रु. (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 324% अधिक) कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 हेतु, इन कार्यों के लिए अभी तक का उच्चतम बजट परिव्यय 3,865 करोड़ रु. प्रदान किया गया है जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 340% अधिक है।

वर्ष 2014-22 के दौरान, तमिलनाडु राज्य में पड़ने वाले 1,066 किमी खंडों (18 किमी नई लाइन, 404 किमी आमाम परिवर्तन और 644 कि.मी. दोहरीकरण) को 133.25 किमी प्रति वर्ष की औसत दर पर कमीशन कर दिया गया है।

किसी रेल परियोजना(ओं) का समय पर पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना(ओं) क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त बाध्यताओं के साथ, परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) रेल मंत्रालय में गति शक्ति निदेशालय और मंडलों में गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरीयों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।
